सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

जल है तो कल है

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-6 • 14 FEBRUARY TO 20 FEBRUARY 2025 • VOLUME 30 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

"जीवन ना तो भविष्य में है, और ना ही भूतकाल में है, जीवन तो सिर्फ वर्तमान में ही है।"

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &
*Pay Money after the Visa

•IELTS •STUDY ABROAD

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.

*T&C apply

मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन

चार दिन पहले मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा

नई दिल्ली. मणिपुर में गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चार दिन पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय शासन की घोषणा करते हुए गृह मंत्रालय के ज़रिए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राय है कि 'ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल सकती।' अधिसूचना में कहा गया है, 'अब संविधान के अनुच्छेद 356 के ज़रिए प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में मुझे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं घोषणा करती हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को अपने ऊपर लेती हूं।'

भारतीय जनता पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और विधायकों के बीच कई दौर की चर्चा के बावजूद भाजपा सीएम पद के लिए नए नेता के नाम की घोषणा

करने में विफल रही। पात्रा ने पिछले दो दिन में राज्यपाल से दो बार मुलाकात की। पात्रा ने 11 फरवरी को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ए. शारदा देवी के साथ भल्ला से बातचीत की और बुधवार को उन्होंने फिर राज्यपाल से मुलाकात की।

ज़िक्रयोग्य है कि मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के लगभग 21 महीने बाद एन. बीरेन सिंह ने अपना पद छोड़ दिया था। इस हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। केंद्र सरकार का कहना है कि वह मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एन. बीरेन सिंह को राज्य में जातीय संघर्ष से निपटने के तरीके को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने पिछले वर्ष मणिपुर में हिंसा को लेकर जनता से माफी मांगी थी।

दरअसल, संकेत मिल रहे थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। ऐसे में सीएम एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे को बड़े सियासी घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा था। सियासी चर्चाओं की मानें तो कांग्रेस मौजूदा नेतृत्व से नाराज कुछ भाजपा विधायकों की मदद से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रही थी।

सीएम चेहरा ना दे पाने की वजह से कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है। कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम लोकेश्वर ने कहा, 'संबित पात्रा का मणिपुर दौरा बेकार है। उन्होंने अब तक कोई बयान तक नहीं दिया।' हालांकि भाजपा विधायक करम श्याम ने कहा कि केंद्र सरकार और विधायक मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे।

वाशिंगटन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने की तुलसी गबार्ड से मुलाकात

वाशिंगटन डीसी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वाशिंगटन में उतरने के बाद नेशनल इंटेलिजेंस की नवनिर्वाचित निदेशक तुलसी गबार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी पहली मुलाकात थी। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी होगी। तुलसी गबार्ड के साथ बैठक की एक झलक साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने उनके साथ भारत-अमेरिका मित्रता पर चर्चा की और ट्रम्प की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनने के लिए उन्हें बधाई भी दी। ट्रंप से मिलने की अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए मोदी ने कहा कि वह इस बैठक और भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं।

लोकसभा में पेश हुआ नया इनकम टैक्स बिल, आयकर भरना होगा आसान

नई दिल्ली. कैबिनेट की मंजूरी के बाद गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश किया। यह विधेयक, जो आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। यह कानूनी भाषा को भी सरल बनाएगा ताकि करदाता प्रावधानों को आसानी से समझ सकें। विधेयक में नए कर नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय, यह कर कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

इसमें छोटे वाक्य, प्रावधान और स्पष्टीकरण होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि नया कानून मौजूदा कानून से 50 फीसदी छोटा होगा. एक प्रमुख लक्ष्य मुकदमेबाजी को कम करना भी है। विधेयक कुछ अपराधों के लिए कम दंड पेश कर सकता है, जिससे कर प्रणाली अधिक करदाता-अनुकूल बन जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात फरवरी को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया।

नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने-समझने में आसान बनाएगा, अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा।

वक्फ बिल रिपोर्ट राज्यसभा में पेश, विपक्षी दलों ने कहा- यह लोकतंत्र विरोधी है

नई दिल्ली. राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद विपक्षी दलों का भारी

हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैंने विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं की जाँच की है। रिपोर्ट में कोई विलोपन या निष्कासन नहीं है। सब कुछ सदन के पटल पर है। ऐसा मुद्दा किस आधार पर उठाया जा सकता है? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं, जो तथ्य नहीं है। आरोप झूठा है। जेपीसी ने पूरी कार्यवाही नियमानुसार की। जेपीसी के सभी विपक्षी सदस्यों ने पिछले 6 महीनों में सभी कार्यवाही में भाग लिया। सभी असहमति नोट रिपोर्ट के परिशिष्ट में संलग्न हैं। वे सदन को गुमराह नहीं कर सकते। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा के बीच विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति रिपोर्ट है। उन नोटों को हटाना और हमारे विचारों को कुचलना सही नहीं है। यह लोकतंत्र विरोधी है। मैं असहमति रिपोर्ट को हटाकर पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्टों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं हैं, तो इसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया।

'आप' सरकार पर पंजाब की महिलाओं का 36,000 करोड़ बकाया : बाजवा

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर पंजाब की महिलाओं का 36,000 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा, '18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह वजीफा देने का आप सरकार का बहुचर्चित कार्यक्रम लंबे समय से लंबित है। मैंने इस बात की पुरजोर वकालत की कि आप सरकार को महिलाओं को तीन साल का बकाया देने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि मूल वादा सरकार बनाने के बाद शुरू करने का था।

एएसआई और उसके बिचौलिए को रिश्वत लेते किया काबू

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत गुरुवार को ईवीएस साउथ अमृतसर में तैनात एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) गुरमीत कौर और उसके साथी हरप्रीत सिंह, जो कि एक व्यक्ति है, को 40,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज्य विजीलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आरोपियों को अमृतसर जिले की तहसील बाबा बकाला के गांव वज़ीर भुल्लर के निवासी सिकंदर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले की आगे जांच जारी है।

10,000 रुपये रिश्वत लेते पीएसपीसीएल का जेई काबू

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने गुरदासपुर जिले के सब-डिवीजन कादियां में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर (जे.ई.) जतिंदर सिंह को 10,000 रुपये रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज्य विजीलैंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को कादियां के मोहल्ला तरखाणवाली के निवासी कश्मीर सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले की आगे की जांच विजीलैंस ब्यूरो यूनिट, गुरदासपुर द्वारा की जा रही है।

स्वास्थ्य कर्मचारी 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

सिविल अस्पताल, लुधियाना के इमरजेंसी वार्ड में तैनात सहायक सतिंदर कुमार को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को जस्सल कॉलोनी, लुधियाना के निवासी विजय कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो की आर्थिक अपराध शाखा के थाना लुधियाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे जांच जारी है।

मान सरकार का छह लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा तोहफा

मंत्रीमंडल ने 14,000 करोड़ रुपए का बकाया जारी करने को दी मंजूरी, विधानसभा की दो दिवसीय विशेष बैठकें 24-25 फरवरी को

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

राज्य सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्री मंडल ने आज उनको 14,000 करोड़ रुपए के बकाए जारी करने को सहमति दी है। इस संबंधी निर्णय आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्री मंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार के तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक के समय की संशोधित वेतन/पेंशन और लीव इनकैशमेंट का बकाया और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक के डी.ए./डी.आर. का बकाया जारी करने की अनुमति दी है। इस बकाये के लिए 14000 करोड़ रुपए की राशि चरणबद्ध रूप से जारी की जाएगी जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को अत्यधिक आवश्यक राहत मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने पंजाब विधान सभा की विशेष बैठकें 24 और 25 फरवरी को बुलाने की अनुमति दी है। इस दो दिवसीय सत्र के दौरान विधायी कार्य किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पटियाला में शिक्षण संकाय को यू.जी.सी. स्केल देने के लिए भी हरी झंडी दे दी है।

सरकारी और निजी क्षेत्र में 60 हजार पदों का सृजन : मंत्रिमंडल ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए राज्य में 22 नई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण में नए पदों के सृजन की

अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने नए बने जिले मलेरकोटला में सहायक निदेशक, सीनियर सहायक और सेवादार के तीन नए पदों के सृजन की भी अनुमति दी। राज्य में कर चोरी रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने कर विभाग में 476 नए पदों के सृजन की अनुमति भी दी है। इसी के साथ विभाग में इंस्पेक्टरों के पदों का नाम बदलने को हरी झंडी दे दी, जिससे अब विभाग के इंस्पेक्टरों को स्टेट टेक्सेशन अफसर (राज्य कर अधिकारी) के रूप में जाना जाएगा। मंत्रिमंडल ने आबकारी विभाग में नियमित आधार पर 53 ड्राइवरों की भर्ती के लिए भी सहमति दे दी। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों (पी.टी.आई. शिक्षकों) की सीधी भर्ती के लिए नियमों और योग्यताओं में संशोधन के लिए भी हरी झंडी दे दी। इससे आने वाले दिनों में राज्य भर में ऐसे 2000 शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में ग्रुप-सी कैडर के 822 पदों के सृजन की भी अनुमति दी है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एस.ए.एस. नगर में विभिन्न कैडरों के 97 पदों के सृजन की भी अनुमति दी है। नौजवानों के लिए रोजगार के 50,000 से अधिक अवसर पैदा करने का उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (ए.के.आई.सी.) परियोजना के हिस्से के रूप में राजपुरा में इंटीग्रेटेड मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आई.एम.सी.) स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 32724 और गैर-औद्योगिक क्षेत्र में 14880 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी।

1500 एकड़ भूमि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर देने के लिए हरी झंडी : मंत्रिमंडल ने "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.वी.एस.) के लिए आरक्षित भूमि का सही उपयोग" पर नीति को मंजूरी दे दी। पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में 1500 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किए गए ईडीसी के सही उपयोग के लिए नीति मंजूर : मंत्रिमंडल ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार की ओर से पापरा एक्ट के तहत अपने परियोजनाओं को विकसित करने वाले प्रमोटरों से एकत्र किए गए ई.डी.सी. के उचित उपयोग की नीति को भी मंजूरी दे दी। इस नीति के अनुसार प्रमोटरों से एकत्र किए गए ई.डी.सी. का 50 प्रतिशत कालोनी या टाउनशिप के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा बड़े परियोजनाओं के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। यह नीति राज्य के विकास को बड़े स्तर पर और बढ़ावा देगी।

तेजाब पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई : मंत्रिमंडल ने तेजाब हमले के पीड़ितों को प्रति माह दी जाने वाली वित्तीय सहायता 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह कर दी है।

डिफॉल्ट हुए आवंटियों के लिए माफी नीति मंजूर : मंत्रिमंडल ने डिफॉल्ट हुए आवंटियों के लिए माफी नीति (एमनेस्टी पॉलिसी) को भी मंजूरी दे दी है। इनमें वे आवंटी शामिल हैं, जो पुडा और अन्य संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा उन्हें आवंटित किए गए प्लॉट/भूमि के पैसे जमा नहीं करा सके। इस नीति के अनुसार डिफॉल्टर अपनी बकाया राशि बिना किसी जुर्माने के स्कीम ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करा सकते हैं। इस स्कीम के तहत गैर-निर्माण खर्च 50 प्रतिशत तक माफ किए जाएंगे और आई.टी. सिटी, एस.ए.एस. नगर में आवंटित किए गए संस्थागत स्थानों/अस्पतालों के लिए प्लॉट/औद्योगिक प्लॉट या विकास प्राधिकरणों की किसी अन्य योजना के मामले में 2.50 प्रतिशत की दर से एक्सटेंशन फीस लगेगी और आवंटियों को आवंटन पत्र की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तीन साल की अवधि दी जाएगी।

हाउसिंग विभाग की ई-नीलामी नीति में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने हाउसिंग और शहरी विकास विभाग की ई-नीलामी नीति में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। सितंबर 2024/अक्टूबर 2024 में की गई ई-नीलामी के बाद प्राप्त फीडबैक के आधार पर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच.एस.वी.पी. और जयपुर विकास प्राधिकरण जैसी अन्य विकास प्राधिकरणों की ई-नीलामी नीतियों को ध्यान में रखने के बाद नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अधिकतम राजस्व उत्पन्न करना है। बड़े स्थानों को छोड़कर सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए योग्यता शुल्कों में वृद्धि की गई है और लगातार दो नीलामियों के बाद न बिकने वाली संपत्तियों की आरक्षित कीमत को कम करने के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है।

लुधियाना में बायो-मीथेन प्लांट स्थापित को हरी झंडी

लुधियाना के बुड्ढा नाले में गोबर के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने औद्योगिक शहर में अत्याधुनिक बायो-मीथेन प्लांट स्थापित करने की अनुमति दे दी है। यह प्लांट 2.5 एकड़ में फैला होगा और इसकी दैनिक क्षमता 300 टन होगी।

पापरा लाइसेंसशुदा परियोजनाओं के लिए समय-सीमा बढ़ाने की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने पापरा लाइसेंसशुदा परियोजनाओं के लिए समय सीमा 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक दो साल के लिए 25,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की विस्तार शुल्क पर बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। इसी तरह मेगा परियोजनाओं के लिए भी 25,000 रुपए प्रति एकड़ की विस्तार शुल्क पर 31 दिसंबर, 2025 तक एक साल का विस्तार करने की मंजूरी दी है। इससे डेवलपर/प्रमोटर को परियोजनाओं को पूरा करने में राहत मिलेगी और परियोजनाओं के आवंटियों को होने वाली कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी।

एनआरआईज के लिए छह विशेष अदालतें

मंत्रिमंडल ने राज्य के छह जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतें स्थापित करने की अनुमति दी है। ये अदालतें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में स्थापित की जाएंगी। इससे प्रवासी भारतीयों को शीघ्र न्याय मिलने की व्यवस्था और बेहतर होगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

ग्रामीण चौकीदारों का मान-भत्ता बढ़ाया

एक और फैसले में मंत्रिमंडल ने ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मान-भत्ता मौजूदा 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की भी मंजूरी दे दी। यह पहल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदारों द्वारा ड्यूटी को और सुचारू रूप से निभाने में मदद करेगी।

मोबाइल से दूर, नेचर के करीब रहना ट्रैवलर्स को आ रहा पसंद

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

घूमने का अपना अलग ही मजा है। ट्रैवलिंग करने के भी अलग-अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग फैमिली या दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते हैं तो कुछ अकेले। किसी को पहाड़ पसंद होते हैं तो किसी को समुद्र। किसी को पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छी लगती हैं तो किसी को ऐसी जगह पसंद हैं जो लोगों की भीड़ भाड़ से दूर हो। आजकल चुपचाप से शांत जगहों पर घूमने का चलन बढ़ रहा है। इसे साइलेंट ट्रैवल कहते हैं।

साइलेंट ट्रैवल को समझें

ट्रैवल एक्सपर्ट निक्की सैनी कहती हैं कि साइलेंट ट्रैवल शब्द सुनकर लगता है कि ऐसी जगह पर घूमना जो सुनसान हो लेकिन ऐसा नहीं है। साइलेंट ट्रैवलिंग एक ऐसी यात्रा है जहां शोर और लोगों की भीड़ नहीं होती। इन जगहों पर जाकर लोगों को सुकून मिलता है। दुनिया भर में इस तरह की घुमक्कड़ी का ट्रेंड बढ़ गया है क्योंकि लोग अब इस ट्रैवलिंग के जरिए डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं। साइलेंट ट्रैवल को quiet travel भी कहते हैं। इसमें ट्रैवलर लोगों से दूर रहकर खुद को नेचर से कनेक्ट करते हैं।

इंट्रोवर्ट लोगों की पहली पसंद

माना जाता है जो लोग कम बोलते हैं या लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं है, वह सोलो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन साइलेंट ट्रैवलिंग भी इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा करते हैं। ऐसे लोग अकेले पहाड़ों पर चढ़ना या समुद्र के किनारे सूरज ढलते देखना पसंद करते हैं।

TRAVELLING

डिजिटल वर्ल्ड में लोगों ने जहां सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के लिए घूमना बढ़ा दिया है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनोखे तरीके से घूमते हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने देते...

ऑफ सीजन है पहली पसंद

अक्सर लोग पीक सीजन में घूमना पसंद करते हैं लेकिन साइलेंट ट्रैवलिंग के शौकीन लोग ऑफ सीजन में घूमना पसंद करते हैं क्योंकि इस समय लोगों की भीड़ नहीं होती। वह इन जगहों को रिलैक्स होकर करीब से देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं।

सोशल मीडिया पर नहीं डालते फोटो

साइलेंट ट्रैवलिंग की एक खूबी है कि ट्रैवलर इस घुमक्कड़ की फोटो कभी सोशल मीडिया पर नहीं डालते। जबकि आजकल अधिकतर लोग केवल सोशल मीडिया पर शो ऑफ के चक्कर के घूमते हैं। साइलेंट ट्रैवलिंग बिल्कुल खामोशी से होती है, दुनियावालों को बिना बताए।

इन जगहों पर जाकर मिल सकती है शांति

अक्सर ट्रैवलर पॉपुलर डेस्टिनेशन में घूमना पसंद करते हैं लेकिन साइलेंट ट्रैवलिंग में वह जगहें शामिल होती हैं जो गुमनाम

होती हैं यानी अधिकतर टूरिस्ट ऐसी जगहों पर नहीं जाते। जैसे अधिकतर लोग समुद्र और सनसेट को देखने ग्रीस या मालदीव जाना पसंद करते हैं लेकिन वही खूबसूरत नजारा अल्बानिया में भी दिखता है लेकिन यह जगह सैलानियों के बीच पॉपुलर नहीं है। भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट, हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली और तोश पार्वती वैली, लद्दाख में हंगले, केरल में पूवर आइलैंड, जम्मू-कश्मीर में युसमर्ग और गुरैज, उत्तराखंड में लैंडोर जैसी जगहें साइलेंट ट्रैवल के लिए बेस्ट हैं।

टेक्नोलॉजी से दूर

साइलेंट ट्रैवलिंग की सबसे खास बात यह है कि लोग इस दौरान टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। घूमने के दौरान वह ना मोबाइल, ना टैब और ना ही लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। वह फोन पर बात करने या वॉट्सऐप पर चैटिंग की जगह लोकल लोगों से कनेक्ट होते हैं। उनसे बात करते हैं और उनके जैसे रहते हैं।

नेचर के करीब रहना फायदेमंद

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से घिरा हुआ है। साइलेंट ट्रैवलिंग में नेचर को करीब से देखा जाता है, उसे महसूस किया जाता है जिससे बॉडी में कार्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है और मूड अच्छा होता है। इस तरह की ट्रैवलिंग से मेंटल हेल्थ भी दुरुस्त रहती है और डिप्रेशन-एंग्जाइटी जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। घूमने के दौरान कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है जिससे फिजिकल हेल्थ भी सुधरती है। वहीं नेचर के करीब रहने से दिमाग क्रिएटिव बनता है, नए-नए आइडिया आते हैं और जिंदगी की कई उलझनें दूर होती हैं।

ब्लड प्रेशर रहता है कंट्रोल

हार्वर्ड हेल्थ की स्टडी के अनुसार घूमने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है। क्योंकि घूमने के दौरान व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। इसके अलावा नींद भी सुधरती है। शहरों की भागदौड़ के बीच लोगों की सबसे ज्यादा नींद ही प्रभावित होती हैं। नेचर के करीब रहने और शांत माहौल से नींद समय पर आती है। दरअसल इस दौरान शरीर की जैविक घड़ी नेचर के हिसाब से काम करती है। सूरज उगते ही नींद खुल जाती है और शाम ढलते ही नींद आने लगती है। वहीं नींद को डिस्टर्ब करने के लिए डिजिटल गैजेट्स भी नहीं होते।

COOKING

शांत रहकर क्यों पकाना चाहिए खाना, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

खाना बनाते समय हर कोई अलग-अलग चीजों को करना पसंद करते हैं जैसे फोन पर बात करना, गाने सुनना या फिर टीवी सीरियल देखना लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गलत है। यहां जानिए कि खाना शांत रहकर क्यों पकाना चाहिए।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

खाना पकाना दिन भर के रूटीन का एक जरूरी हिस्सा है। खाना पकाने का हर किसी का अपना तरीका है। कुछ लोग फोन पर बात करते हुए कुकिंग करना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग फोन पर सीरियल देखते हुए खाना पकाते हैं तो वहीं कुछ ऐसे हैं जो तेज आवाज में गाने सुनते हुए खाना पकाते हैं। लेकिन क्या इस तरह से खाना पकाना सही है? इस तरह से खाना पकाना बिल्कुल सही नहीं है।

शांत रहकर खाना पकाना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इस तरह आप ज्यादा फोकस होते हैं। इसके अलावा खाने को देखने के साथ उसकी खुशबू, बनावट और आवाज के साथ पूरी तरह से जुड़ने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा इस तरह की कुकिंग आपको स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स महसूस करवा सकती है। यहां जानिए शांत रहकर खाना पकाने से क्या होता है-

स्ट्रेस होगा कम

जब आप शांत रहकर खाना पकाते हैं तो शांत वातावरण तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसी के साथ अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एकांत का मजा लेते हैं शांत रहकर खाने बनाने का अनुभव आपको जरूर पसंद आएगा।

आवाज के प्रति जागरूकता

खाना पकाते समय जब आप बातचीत या किसी भी तरह के शोर से दूर होते हैं, तो आप खाना पकाने की हल्की आवाज जैसे तेल के गर्म होने, उबलते पानी की आवाज सुन पाते हैं। इसी के साथ सब्जियों को धीरे से काटने में ज्यादा मशगूल हो जाते हैं। ऐसा करके आप खाना पकाने की प्रक्रिया की ज्यादा सटीक निगरानी कर सकते हैं।

माइंडफुलनेस प्रेक्टिस

अगर आपके दिमाग में हमेशा बहुत कुछ चलता रहता है तो शांत रहकर खाना पकाना एक तरह की माइंडफुलनेस प्रेक्टिस हो सकती है, जो आपको उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने और काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। ऐसा करके आप ज्यादा आराम और केंद्रित महसूस करते हैं।

खाने का बढ़ता है स्वाद

खाना बनाते समय आवाज और खाने की बनावट पर पूरा ध्यान देने से आपको अपने खाने की अच्छी बनावट मिल सकती है। इसी के साथ आप खाने को बहुत ज्यादा पकने या जलने से बचा सकते हैं।

हार्ट अटैक की वजह बन सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने में मदद करेंगी चटनियां

अगर आपको भी बैड कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है तो अपनी डाइट में इन 5 तरह की चटनियों को जरूर शामिल करें। ये सभी चटनियां ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती हैं बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को भी

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

सुस्त लाइफस्टाइल और खानपान की बिगड़ी हुई आदतें आजकल सेहत से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का कारण बन रही हैं। ऐसी ही एक समस्या का नाम बैड कोलेस्ट्रॉल है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता लेवल हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याओं को खतरा बढ़ाकर व्यक्ति की सेहत को खराब कर सकता है। चिंता की बात यह है कि अगर इस समस्या पर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए व्यक्ति को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपको भी बैड कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है तो अपनी डाइट में इन चटनियों को जरूर शामिल करें। ये सभी चटनियां ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती हैं बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को भी बैलेंस करने में मदद करती हैं।

बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखती हैं ये 5 चटनियां

पुदीने की चटनी : चटपटी पुदीने की चटनी ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को भी बैलेंस करने में मदद करती हैं। पुदीने में मौजूद फाइबर और क्लोरोफिल पाचन के लिए फायदेमंद होने के साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं। इस चटनी को दिन में एक बार डाइट में जरूर शामिल करें।

मेथी चटनी

मेथी की चटनी में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। मेथी की चटनी में मौजूद फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, और अन्य पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। मेथी के पत्तों से चटनी ही नहीं सब्जी,रोटी, पराठे, मुठिया जैसी चीजें भी बनाकर खाई जा सकती हैं।

पालक चटनी

पत्तेदार पालक में कई ऐसे पौष्टिक गुण मौजूद होते है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। पालक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। ये हार्ट की धमनियों में खून के थक्के जमने की संभावना कम करके बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में

मदद करता है। इस चटनी को बनाने के लिए आप इसमें पालक के पत्तों के साथ हरा धनिया और पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं।

बथुआ चटनी

बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने के लिए बथुआ की सब्जी ही नहीं बल्कि चटनी भी बेहद फायदेमंद हो सकती है। बथुए में मौजूद फाइबर और रफेज, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने के साथ पाचन तंत्र को भी अच्छा बनाए रखता है।

करीपत्ते की चटनी

करीपत्ते में मौजूद कई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी औषधीय गुण बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। आप इसे सब्जी में डालने के साथ इसकी चटनी भी बनाकर खा सकते हैं।

बच्चे में डालनी हैं हेल्दी खाने की आदत? सीख लें मनोचिकित्सक की बताई ये ट्रिक्स

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

पोषण के कुछ निवाले नन्हे पेट तक पहुंचाने की जिस जद्दोजहद से आप रोज गुजरती हैं, वो कभी खीज तो, कभी चिंता बनी नजर आती है। आपकी शिकायत हर बार यही कि वह खाता नहीं है। एक बार जो चीज वह चाव से खाता है, अगली बार वही उसे रास नहीं आती वगैरह। माना कि आपकी प्राथमिकता पोषण है, पर बच्चे को यह बात समझ कैसे आए? इसके लिए आपको कुछ जुगत लगानी होगी, कुछ सूत्र गढ़ने होंगे ताकि उनकी मदद से आपकी बात आपका बच्चा समझ सके और अपनी खानपान के आदतों में सुधार कर सके।

रंग आएंगे काम : साइकोलॉजिस्ट कहती हैं कि बच्चों में स्वस्थ खानपान की आदत को विकसित करने के लिए, रंग-बिरंगे व्यंजन बनाइए। लक्ष्य तय कीजिए कि हफ्ते के हर दिन इंद्रधनुष के रंगों में से किसी एक रंग का खाना उन्हें परोसा जाए। साथ ही उनकी थाली को आकर्षक बनाने के लिए कुछ प्रयोग भी कर सकती हैं, जैसे उसकी थाली में छोटी और पतली रोटी रखें, उसकी शेप में प्रयोग कर सकती हैं।

सबके साथ परोसें खाना : जब हम सबके साथ खाना खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं। ऐसा बच्चों के साथ भी मुमकिन है। सबके साथ बच्चों की खुराक बढ़ जाती है। यहां यह भी जरूरी है कि उनको भी वही सर्व किया जाए जो बाकि लोग खा रहे हों।

जरूरी बातें : बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो उनके साथ ही किचन के सामान की शॉपिंग करें। इस दौरान आपको उनकी पसंद जानने का मौका मिलेगा। साथ ही आप शॉपिंग के दौरान उन्हें पोषक तत्वों के बारे में भी बता पाएंगी।

दूध में कटौती है जरूरी। जब बच्चा खाने लायक हो जाए तो उसे दिन में सिर्फ दो बार ही दूध देना चाहिए। अधिक दूध पीने से उसका रुझान खाने की तरफ नहीं पनप पाता और वह जरूरी पोषक तत्वों से वंचित रह जाता।

नाश्ते में पैक्ड फूड यानी जूस, ब्रेड, नूडल्स आदि बच्चों को नहीं देना चाहिए। इनमें मौजूद शर्करा, प्रिजरवेटिव्स बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि पर दुष्प्रभाव डालते हैं।

रात के खाने के बाद चॉकलेट और आइसक्रीम सरीखी चीजें न दें। रात का खाना सोने के पहले की आखिरी खुराक होती है। चॉकलेट, आइसक्रीम आदि नींद पर असर डालते हैं, जो कि शारीरिक और मानसिक विकास पर असर डालते हैं।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

महिलाएं इन आदतों की वजह से उम्र से पहले लगती हैं बूढ़ी

HEALTH

महिलाओं में इस तरह की 5 आदतें उन्हें उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखाना शुरू कर देती हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

अपने आसपास अक्सर देखने को मिलता है कि महिलाएं उम्र से पहले ही बूढ़ी नजर आने लगती हैं। शरीर में ढेर सारी बीमारियों के साथ ही स्किन पर भी झुर्रियां सी दिखने लगती हैं। अगर महिलाएं चाहती हैं कि वो समय से पहले बुढ़ापा ना झेलें और हेल्दी बनी रहें तो इन आदतों को आज से ही फौरन छोड़ दें।

एक्सरसाइज ना करना

महिलाओं को लगता है कि वो घंटों खड़े होकर काम करती हैं तो उन्हें एक्सरसाइज की क्या जरूरत। जबकि एक्सरसाइज हर बॉडी की जरूरत है। अगर आप घंटों खड़ी रहती हैं तो बैठकर और अपने पैरों को मजबूत बनाने की एक्सरसाइज की जरूरत है। जिससे कि आप उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों से ना घिरें और हेल्दी बनी रहें। हार्ट हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है।

हमेशा चिंता करना

महिलाएं अक्सर फ्यूचर को लेकर, लोगों की सोच को लेकर या फिर किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करती रहती हैं। स्ट्रेस, टेंशन और तनाव बॉडी में कार्टिसोल का लेवल बढ़ाता है। जो कई सारी बीमारियों की वजह बनता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा चिंता ना करने की आदत छोड़ दें।

बहुत गुस्सा होना

गुस्सा, चिड़चिड़ापन अगर हमेशा बना रहता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचाता है। निगेटिव इमोशन आपकी स्किन और बालों पर दिखते हैं। जिससे आप उम्र से पहले ही बूढ़ी दिखने लगेंगी।

पानी कम पीना

घर और परिवार की चिंता में ज्यादातर महिलाएं खुद का ध्यान नहीं रखतीं। यहां तक पानी भी बहुत कम पीती है। कई बार मेनोपॉज या डिलीवरी के बाद ब्लैडर वीक होने की वजह से यूरिन लीक की प्रॉब्लम होने लगती है। जिससे महिलाएं पानी पीना कम कर देती हैं और इससे स्किन और बालों की हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ता है। वहीं हेल्थ प्रॉब्लम भी होने लगती है। इसलिए आज से ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शुरू कर दें।

नींद कम लेना

घर के कामों की वजह से नींद को खराब ना करें। कम नींद हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है। जब आप सोती हैं तो बॉडी खुद को रिपेयर करती हैं और एजिंग स्पीड कम होती है। तो अगर समय से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहती हैं तो पर्याप्त मात्रा में नींद लेने की आदत डालें।

नोट : *इस खबर में बताए गए सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। इसलिए किसी भी उपचार/दवा/डाइट को अमल करने से पहले डाक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।*

पीएम मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन पर अपने विचार व्यक्त किए। यशोभूमि में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपस्थित लोग न केवल ऊर्जा सप्ताह का हिस्सा हैं, बल्कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का अभिन्न अंग भी हैं।

भारत ऊर्जा सप्ताह की परिकल्पना अन्य उद्योग सम्मेलन से कहीं अधिक के रूप में की गई थी- इसे वैश्विक ऊर्जा संवादों को फिर से परिभाषित करने वाले एक गतिशील मंच के रूप में डिजाइन किया गया था। केवल दो वर्षों में, इस स्व-वित्तपोषित पहल ने यह हासिल किया है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम बन गया है। 11-14 फरवरी, 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में निर्धारित भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 वैश्विक ऊर्जा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की है, मोदी ने कहा, "भारत न केवल अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ दुनिया के विकास को भी आगे बढ़ा रहा है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं पांच स्तंभों पर टिकी हैं: संसाधनों का दोहन, प्रतिभाशाली के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता, ऊर्जा व्यापार को आकर्षक और आसान बनाने वाली रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और वैश्विक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कारक भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

मोदी ने कहा, "पिछले एक दशक में देश दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दस वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बत्तीस गुना बढ़ गई है, जिससे यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तीन गुना बढ़ गई है और भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला पहला जी20 देश है। प्रधानमंत्री ने इथेनॉल मिश्रण में भारत की उपलब्धियों पर जोर दिया, जिसकी वर्तमान दर उन्नीस प्रतिशत है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आई है। उन्होंने अक्टूबर 2025 तक बीस प्रतिशत इथेनॉल अनिवार्यता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत का जैव ईंधन उद्योग 500 मिलियन मीट्रिक टन स्थायी फीडस्टॉक के साथ तेजी से विकास के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना की गई थी और यह लगातार विस्तार कर रहा है, जिसमें अब 28 राष्ट्र और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह गठबंधन कचरे को आय में बदल रहा है और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत अपने हाइड्रोकार्बन संसाधनों की क्षमता का पूरी तरह से पता लगाने के लिए लगातार सुधार कर रहा है, मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रमुख खोजें और गैस अवसंरचना का व्यापक विस्तार गैस क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहा है,

जिससे भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है और अपनी क्षमता को 20 प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के तलछटी बेसिनों में कई हाइड्रोकार्बन संसाधन हैं, जिनमें से कुछ की पहचान पहले ही हो चुकी है, जबकि अन्य की खोज की प्रतीक्षा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के अपस्ट्रीम क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) शुरू की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने इस क्षेत्र को व्यापक समर्थन दिया है, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र खोलना और एकल खिड़की निकासी प्रणाली स्थापित करना शामिल है। मोदी ने कहा कि तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास अधिनियम में किए गए बदलावों से अब हितधारकों को नीतिगत स्थिरता, विस्तारित पट्टे और बेहतर वित्तीय शर्तें मिल रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन सुधारों से समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस संसाधनों की खोज में मदद मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाए रखने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई खोजों और पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ रही है। इससे निकट भविष्य में प्राकृतिक गैस के उपयोग में वृद्धि होगी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इन क्षेत्रों में निवेश के कई अवसर हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में इस आयोजन के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला, जो महज तीन वर्षों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन बन गया है। इस वर्ष के आयोजन में 50 से अधिक देशों के 70,000 से अधिक ऊर्जा पेशेवरों ने हिस्सा लिया है, जिसमें फॉर्च्यून 500 ऊर्जा कंपनियों के 20 से अधिक मंत्री और 100 सीईओ शामिल हैं, जिससे यह उभरते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है।

पुरी ने कहा कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को नया रूप देने वाले प्रमुख भू-राजनीतिक बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सम्मेलन नीति निर्माताओं, प्रसिद्ध उद्योगपतियों और हितधारकों को सार्थक संवाद में शामिल होने, विचारों का आदान-प्रदान करने और संतुलित और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक मार्ग तैयार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवर्तन व्यावहारिक होना चाहिए, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन और जैव ईंधन के साथ-साथ हाइड्रोकार्बन की निरंतर भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024 तक वैश्विक ऊर्जा निवेश 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा, जिसमें से 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए समर्पित होंगे, जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से हो रहे बदलाव का स्पष्ट संकेत है।

मंत्री महोदय ने ऊर्जा नवाचार और उद्यमिता को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि बीपी, शेल, एक्सॉनमोबिल और शेवरॉन जैसी प्रमुख वैश्विक ऊर्जा फर्म भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र संचालित करती हैं, जो ऊर्जा दक्षता, डेटा एनालिटिक्स और स्थायी संचालन के लिए अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए हजारों भारतीय इंजीनियरों को रोजगार देती हैं। उन्होंने अविन्या और वसुधा जैसी स्टार्ट-अप चुनौतियों में भाग लेने वाले 500 से अधिक उद्यमियों और एआई-संचालित ऊर्जा समाधान, क्वांटम कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों और जैव ईंधन और बैटरी प्रौद्योगिकियों में प्रगति का प्रदर्शन करने वाली 100 से अधिक स्टार्ट-अप सहित 700 प्रदर्शनी कंपनियों की भूमिका को भी स्वीकार किया।

उनके संबोधन का एक प्रमुख विषय ऊर्जा न्याय था, जहां उन्होंने खंडित ऊर्जा नीतियों के खिलाफ चेतावनी दी जो संक्रमण में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर असमानता को गहरा कर सकती हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर बल दिया तथा प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यवधानों को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाने, अपने गैस हिस्से को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने और 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखने सहित विविध ऊर्जा स्रोतों में रणनीतिक रूप से निवेश कर रहा है, ताकि ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किए बिना एक सहज संक्रमण सुनिश्चित किया जा सके।

पुरी ने कहा कि सभी हितधारकों से भारत ऊर्जा सप्ताह को परिवर्तनकारी साझेदारी बनाने और वैश्विक ऊर्जा एजेंडे को आकार देने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने 6,000 से अधिक प्रतिनिधियों को अगले चार दिनों में सम्मेलन की चर्चाओं में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने, तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वैश्विक ऊर्जा इको-सिस्टम में भारत की बढ़ती केंद्रीय भूमिका के साथ, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ऊर्जा के भविष्य को परिभाषित करने के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है।

केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 : वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा

भारतीय परिधान और वस्त्र उद्योग लगभग 176 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है। यह विनिर्माण उत्पादन का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है। वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, यह प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक वस्त्र श्रमिकों को रोजगार देता है। भारत वस्त्र और परिधानों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत है। देश के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान (टी एंड ए) की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 8 प्रतिशत है। यह क्षेत्र मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण युवा रोजगार जैसी सरकार की प्रमुख पहलों के साथ पूरी तरह से संरेखित है।

बजट में वर्ष 2025-26 के लिए वस्त्र मंत्रालय के लिए 5,272 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई। यह वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों (4417.03 करोड़ रुपये) की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि थी, और हाल के वर्षों में यह सबसे अधिक है। वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी निवेश योजना का बजट वर्ष 2024-25 में 45 करोड़ रुपये (बीई) से बढ़ाकर इस वर्ष 1148 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और पांच वर्ष की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत वित्तीय परिव्यय के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। यह मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ), एमएमएफ परिधान और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र जैसे उभरते क्षेत्रों को कवर करता है, ताकि इन क्षेत्रों को आकार और पैमाने हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके, ताकि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें।

केंद्रीय बजट वर्ष 2025-26 में 'कपास उत्पादकता के लिए मिशन' की घोषणा की गई है। यह 5 वर्षीय मिशन कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। यह अतिरिक्त लंबे स्टेपल वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देगा। इस मिशन को कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।

वस्त्र मंत्रालय का राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (i) अनुसंधान, नवाचार और विकास, (ii) संवर्धन और बाजार विकास (iii) शिक्षा और कौशल तथा (iv) तकनीकी वस्त्रों में निर्यात संवर्धन पर केंद्रित है। बजट में दो और प्रकार के शटल-लेस लूम को पूरी तरह से छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी की सूची में जोड़ा गया है। वस्त्र उद्योग में उपयोग के लिए शटल-लेस लूम रैपियर लूम (650 मीटर प्रति

जालंधर ब्रीज

गिरिराज सिंह
(केंद्रीय वस्त्र मंत्री)

मिनट से कम) और शटल-लेस लूम एयर जेट लूम (1000 मीटर प्रति मिनट से कम) पर शुल्क मौजूदा 7.5 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया है।

नौ टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आने वाले बुने हुए कपड़ों पर बुनियादी सीमा-शुल्क दर को "10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत" से बढ़ाकर "20 प्रतिशत या 115 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" करने की बजट घोषणा से बुने हुए कपड़ों के सस्ते आयात पर अंकुश लगाकर घरेलू वस्त्र उद्योग को मजबूती मिलेगी। यह उपाय घरेलू स्तर पर उत्पादित कपड़ों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा, क्षमता उपयोग को बढ़ावा देगा और स्थानीय विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए एक स्रोत के रूप में पहचाना गया है। यह वस्त्र क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की वस्त्र और परिधान उत्पादन क्षमता का अधिकांश हिस्सा एमएसएमई द्वारा किया जाता है, जो इस क्षेत्र का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन जैसे प्रावधान गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ उन्हें पैमाने की उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करेंगे। संशोधित वर्गीकरण के साथ, अब अधिक इकाइयाँ एमएसएमई के अंतर्गत आएंगी।

उपरोक्त एजेंडे को आगे बढ़ाने और भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, एक मेगा इवेंट - भारत टेक्स 2025, 11 प्रमुख वस्त्र उद्योग निकायों द्वारा आयोजित किया जा रहा है और वस्त्र मंत्रालय द्वारा समर्थित है। भारत टेक्स 2025 विस्तार और लक्ष्य दोनों के लिहाज से दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि यह कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों और सहायक उपकरणों सहित पूरे वस्त्र उद्योग मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। अनुकूल वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और वस्त्र स्थिरता के दोहरे विषयों के आसपास निर्मित - यह कार्यक्रम स्थिरता, नवाचार और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित है।

मुख्य कार्यक्रम 14-17 फरवरी, 2025 को भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसमें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक वस्त्रों की पूरी मूल्य श्रृंखला को सक्षम नीति समर्थन के साथ कवर किया जाएगा, जबकि सहायक उपकरण, परिधान मशीनरी, रंग और रसायन तथा हस्तशिल्प जैसी संबंधित प्रदर्शनियां 12 से 15 फरवरी, 2025 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाएंगी। संपूर्ण कच्चे माल मूल्य श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, अधिक निवेश प्राप्त करने, अपने घरेलू बाजार के आकार और निर्यात को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता को बनाए रखने एवं बढ़ाने के प्रयासों को सक्षम नीति समर्थन के साथ और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता होगी।

अरुणाचल और अक्साई चिन को भारत में दिखाने पर चीन को लगी मिर्ची, बांग्लादेश ने दिया मुंहतोड़ जवाब

• **जालंधर ब्रीज** . वर्ल्ड न्यूज

अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा बताए जाने पर चीन को मिर्ची लग गई है। बांग्लादेश की दो किताबों और डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे की वेबसाइट पर छपे एशिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को भारत में दिखाया गया था, जिसको लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज करवाई। मालूम हो कि दोनों ही हिस्से भारत के हैं, जिसपर आदत से मजबूर चीन विवाद खड़ा करता रहता है। हालांकि, इस मामले को लेकर बांग्लादेश ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और कोई भी बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया। ढाका ने बीजिंग से इस मामले में उसके ऊपर दबाव नहीं डालने को कहा है।

इसके अलावा, किताबों और वेबसाइट के मैप में हांगकांग और ताइवान को भी स्वतंत्र देश की तरह दिखाया गया, जिसको लेकर भी चीन ने चिंता जाहिर की। दोनों ही देशों को चीन अपना बताता रहा है। बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट 'प्रोथोमालो' ने दावा किया है कि राजनयिक सूत्रों ने रिपोर्टर को बताया कि चीन ने नवंबर के आखिरी सप्ताह में बांग्लादेश को एक लेटर भेजा था, जिसमें किताबोंऔर सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पर छपे मैप और सूचनाओं में सुधार का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा भी हुई। हालांकि, बांग्लादेश के अनुरोध के जवाब में चीन ने फिलहाल इस मुद्दे पर दबाव नहीं डाला है।

बांग्लादेश ने दे दिया कड़ा जवाब : सूत्रों के हवाले से बताया गया कि चीन की आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक बोर्ड (एनसीटीबी) से संपर्क किया। इसके बाद एनसीटीबी ने मंत्रालय को बताया कि नई किताबों की प्रिंटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। बांग्लादेश ने हालात को समझाते हुए चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और कोई भी दबाव नहीं डालने के लिए कहा। बांग्लादेश की किताबों और वेबसाइट पर मैप इसी तरह से पहले छपते रहे हैं। वहीं, बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन ने यह मुद्दा इसलिए उठाया है, क्योंकि पांच अगस्त को हुए बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंध खराब हो गए हैं।

झूठे दावे की आदत से मजबूर चीन : बांग्लादेश के इब्तेदाई मदरसा में कक्षा 4 की बांग्लादेश और वैश्विक अध्ययन नाम की किताब में एशिया का मैप है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन की सीमा को भारत में दिखाया गया। इसके अलावा, कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए बांग्लादेश और वैश्विक अध्ययन किताब में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन की एक सूची शामिल है, जिसमें हांगकांग और ताइवान को स्वतंत्र देशों के रूप में दिखाया गया है। उल्लेखनीय है कि चीन की विस्तारवादी नीति और झूठे दावे से पूरी दुनिया परेशान है। भारत का पड़ोसी होने की वजह से ड्रैगन कई झूठे दावे करता रहता है। कभी वह पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर टेंशन पैदा करता है तो कभी अरुणाचल प्रदेश पर गलत दावे करता है। इसके अलावा, साउथ चाइना सी, ताइवान, हांगकांग आदि को लेकर भी चीन और अन्य देशों के बीच विवाद होते रहते हैं।

परीक्षा योद्धाओं की नई परिभाषा : परीक्षा के युद्धक्षेत्र से परे

प्रकृति ने अपनी असीम बुद्धि से प्रत्येक मनुष्य को एक अलग पहचान दी है - हमारी उंगलियों के निशान से लेकर आंखों की पुतलियों तक, हमारे अनुभव से लेकर विचारों तक, हमारी प्रतिभाओं से लेकर उपलब्धियों तक। मानवीय विशिष्टता के बारे में यह गहन सत्य हमारे समाज की विशेषता रही है और हमारी शिक्षा प्रणाली को इस विशेषता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे में कुछ जन्मजात प्रतिभा होती है, कुछ शैक्षिक प्रतिभा से चमकते हैं, अन्य रचनात्मकता के लिए तत्पर होते हैं, कई अन्य एथलेटिक और पेशेवर कौशल से युक्त होते हैं। इस विशिष्टता को दर्शाते हुए, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, "शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है।"

एक बच्चे की प्राकृतिक प्रतिभा को निखारना और उसे उसकी पसंद के शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों में रचनात्मक रूप से शामिल करना हमारे शैक्षणिक संस्थानों के सामने कठिन चुनौतियां रही हैं। शिक्षकों और नीति निर्माताओं के रूप में हमारी भूमिका एक बच्चे की अनूठी प्रतिभा को विकसित करना है, जिससे वह चुने हुए लक्ष्य में श्रेष्टता प्राप्त कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने प्रतिभा को परिभाषित करने और उसको विकसित करने के तरीके में एक विलक्षण बदलाव किया है। यह एक दार्शनिक ढांचा है जो वास्तव में हमारे प्रत्येक बच्चे में मौजूद विशिष्टता की सूक्ष्म रूपरेखा का वर्णन कर सकता है जो हमारे देश की उन्नति में योगदान देता है।

हमारे प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम शिक्षा में संपूर्ण सुधार लागू कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे की शैक्षिक यात्रा हमेशा रोमांचकारी और यादगार बनी रहे। बच्चे पढ़ाई और परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के तनाव और दबाव से मुक्त रहें। यह दृष्टिकोण हमारे शैक्षिक सुधारों का केंद्र है, बुनियादी शिक्षा से लेकर शिक्षा और अनुसंधान के उच्चतम स्तरों तक।

कुछ साल पहले, हमारे युवा शिक्षार्थियों के लिए बाल वाटिका या खिलौना-आधारित शिक्षा ने व्यापक संदेह को आमंत्रित किया होगा। आज, एनईपी की बदौलत, ये अभिनव दृष्टिकोण प्रारंभिक शिक्षा में आमूल परिवर्तन ला रहे हैं, जिससे सीखना कष्टदायक होने के बजाय एक आनंददायक कार्य बन गया है। हमारी नई शिक्षा प्रणाली यह मानती है कि प्रत्येक बच्चा अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के अनुसार विकास करता है।

हमारी क्रेडिट ट्रांसफर नीति जो एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित करती है, एक और उन्नतिशील कदम आगे बढ़ाती है। यह माना जाता है कि जीवन का मार्ग हमेशा सीधा नहीं हो सकता है, बल्कि इसमें उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं और सीखना विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न गति से हो सकता है। शिक्षार्थी औपचारिक शिक्षा को रोक सकते हैं क्योंकि वे अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं तथा अपने परिवार का समर्थन करते हैं। जब वे औपचारिक शिक्षा में वापस लौटते हैं, तो उनके अपने

जालंधर ब्रीज

धर्मेंद्र प्रधान
(केंद्रीय शिक्षा मंत्री)

अनुभव और उपलब्धियां काम आती हैं और इन्हें महत्व दिया जाता है जो उनके क्रेडिट अकादमिक रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। यह अनुकूलनियता इस बात को जोर देती है कि सीखने के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं, जो लोगों को उनके जीवन के किसी भी मोड़ पर सीखने के पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लाते हैं।

सरकार ऐसी संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां परीक्षा में सफलता कभी भी संपूर्ण विकास पर हावी न हो, जिससे हमारे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान न हो। इस महत्वपूर्ण चुनौती को पहचानते हुए, हमारी सरकार ने परीक्षा से संबंधित तनाव को दूर करने में मदद करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। प्रधानमंत्री की अभूतपूर्व "परीक्षा पे चर्चा" पहल छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के मूल्यांकन के तरीके को बदलने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। छात्रों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत ने परीक्षा की चिंता को राष्ट्रीय संवाद में बदल दिया है। उन्होंने पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं को लेकर होने वाली चिंता को दूर करने का प्रयास किया है, जो संवेदनशील दिमाग पर अनावश्यक दबाव डालती है।

प्रधानमंत्री के अपने जीवन और अनुभवों से लिए गए व्यावहारिक सुझावों को परीक्षार्थियों ने खूब सराहा है, जिससे उनका परीक्षा में तनाव मुक्त प्रदर्शन आश्वस्त हुआ है। सच्चे नेतृत्व के एक उदाहरण में, हम भारतीयों की भावी पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए एक दूरदर्शी नेता के समर्पण को देख रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है और राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर होना सुनिश्चित करता है। माता-पिता और समाज तथा नागरिक पर ये परिवर्तन केंद्रित है। परीक्षा पे चर्चा मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षण सहायक, वातावरण के महत्व को उजागर करने में परिवर्तनकारी रही है। यह एक ऐसी मानसिकता है जिसे केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड की कक्षाओं के अलावा सभी कक्षाओं और सभी उम्र के छात्रों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए । परीक्षा के समय दबाव और तनाव को दूर करने के सभी चरणों को सिखाया जाना चाहिए।

रवींद्रनाथ टैगोर के बुद्धिमान शब्दों में, "बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित न रखें, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।" शैक्षिक परिवर्तन के प्रति हमारा दृष्टिकोण इसी ज्ञान से निर्देशित है। यह विचार कि शिक्षा में तनाव अनिवार्य है, इस समझ को बदलने की आवश्यकता है कि वास्तविक शिक्षा पोषण करने वाले वातावरण में पनपती है। जब समुदाय, शिक्षक और परिवार मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहां छात्र का विकास हो सकें, तो सफलता अवश्य मिलती है। कक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों से लेकर अनुसंधान प्रयोगशालाओं तक, हमें ऐसे स्थान बनाने चाहिए जहां अलग-अलग प्रतिभाएं अपनी चमक पा सकें और विकास कर सकें। पारंपरिक एक-आकार-सभी-फिट दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि एक से अधिक सूक्ष्म, उत्तरदायी प्रणाली को रास्ता दिया जा सके जो व्यक्तिगत क्षमता को पहचान सके और उसका विकास कर सकती हो।

जैसे-जैसे हम विकासित भारत की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय परिवर्तन की एक प्रमुख आधारशिला के रूप में खड़ी है। हम मानते हैं कि हर कौशल में योग्यता होती है, हर यात्रा का मूल्य होता है, और हर बच्चे को उत्कृष्टता के लिए अपना अनूठा मार्ग खोजने का अधिकार है। जब हम विविध प्रतिभाओं का पोषण करते हैं, हम अपने समाज के ताने-बाने को मजबूत करते हैं और सभी क्षेत्रों में अपने राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाते हैं।

आज, मैं अपने महान राष्ट्र के प्रत्येक माता-पिता, शिक्षक और नागरिक का आह्वान करता हूं। शिक्षा का परिवर्तन केवल एक सरकारी पहल नहीं है - यह एक राष्ट्रीय मिशन है जो हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और साझा दृष्टिकोण की मांग करता है। हम अपने लक्ष्यों को तब प्राप्त करेंगे जब सरकार और नागरिक समाज के बीच सहयोग और साझेदारी हमारी नीतियों और कार्यों को परिभाषित करेगी।

हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। वे अपनी अनूठी प्रतिभा से चमकेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। एक उज्ज्वल भविष्य हमारा आह्वान करता है। हम मानते हैं कि प्रत्येक बच्चे की अद्वितीयता में भारत के भविष्य की विलक्षणता निहित है। तनाव मुक्त शिक्षा हमारे बेहद प्रतिभाशाली छात्रों के अनुपम योगदान को निखारने की कुंजी होगी।

नशे में गाड़ी चलाने और सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस का अभियान

रात 8.00 से 11.00 बजे के बीच 262 वाहनों की जांच की व 33 के काटे चालान

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 फरवरी, 2025 और 12 फरवरी, 2025 को वाहनों में शराब पीने और नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष रात्रि अभियान चलाया। यह ऑपरेशन क्रमशः निर्मल सिंह, पीपीएस, एसीपी सेंट्रल और सिरीवेनेला, आईपीएस, एसीपी मॉडल टाउन, जालंधर की देखरेख में रात 8:00 बजे से 11:00 बजे तक चलाया गया। नई अनाज मंडी और बूटा मंडी जालंधर में यह अभियान चलाया गया। इसका मुख्य लक्ष्य वाहनों के अंदर शराब पीने की व्यापक समस्या से निपटना और नई अनाज मंडी और बूटा मंडी जैसे प्रमुख स्थानों के पास नशे में वाहन चलाने से रोकना था। सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ पुलिस का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि शराब की खपत को नियंत्रित किया जाए, विशेष रूप से शराब की दुकानों और परिसरों के आसपास तथा साथ ही गैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग व्यवहार को रोका जाए।

ट्रैफिक पुलिस/ईआरएस टीम और फील्ड मीडिया टीम (एफएमटी) के सहयोग से एसएचओ डिवीजन नंबर 2 ने इस अभियान का नेतृत्व किया। कुल 262 वाहनों की गहन जांच की गई तथा संदिग्धों में शराब पीने की बात का पता लगाने के लिए श्वास विश्लेषक का प्रयोग किया गया। यह कार्रवाई सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने पर केंद्रित थी, जिससे जिम्मेदाराना व्यवहार के महत्व के बारे में स्पष्ट संदेश दिया गया।

अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए कुल 33 चालान जारी किए। नशे में वाहन चलाने पर 10 चालान किए। बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहनों पर 5 चालान किए। हेलमेट न पहनने वाले 7 व्यक्तियों के चालान काटे गए। दोपहिया वाहन पर तीन लोगों के बैठने संबंधी 8 चालान किए गए। उचित दस्तावेजों के अभाव में 3 वाहन जब्त किए गए। यह अभियान सड़क सुरक्षा में सुधार और अपने निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। यातायात उल्लंघन को कम करने और अवैध गतिविधियों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुलिस जालंधर को एक सुरक्षित शहर बनाने के अपने मिशन पर अडिग है। इसी प्रकार की कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी जिससे यह संदेश मजबूत होगा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जालंधर पुलिस एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए समर्पित है, जहां निवासी असुरक्षित ड्राइविंग या सार्वजनिक खतरे के बिना रह सकें, काम कर सकें और खेल सकें।

बुनियादी ढांचे में 930 करोड़ के निवेश से लुधियाना कायाकल्प को तैयार

लुधियाना में क्रांति: स्मार्ट सड़कों, हरियाली और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए 85 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह की दूरदर्शी अगुवाई में पंजाब के शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इस विकास की प्रमुख मिसाल के रूप में जिला लुधियाना उभरकर सामने आया है। गौरतलब है कि जिले में कुल 85 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत 930 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये परियोजनाएँ शहर के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने, जीवन स्तर को बेहतर बनाने और लंबे समय से चली आ रही शहरी चुनौतियों के आधुनिक समाधान प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं।

ध्यान देने योग्य है कि 712.86 करोड़ रुपये की लागत से 65 प्रमुख परियोजनाएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जो विकास की व्यापक पहल को दर्शाती हैं। इन परियोजनाओं में पखोवाल रोड पर रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) और रेल अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) का निर्माण, सिद्धवां नहर के किनारे वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट, स्मार्ट ई-क्लासरूम की स्थापना, मल्हार रोड को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित करना, और निगरानी व सुरक्षा के लिए एक नगर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कम्पैक्टरों का उपयोग और एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटों की स्थापना भी सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। पार्कों सहित हरियाली बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, 199.26 करोड़ रुपये की लागत से 17 अन्य परियोजनाएँ क्रियान्वयन चरण में हैं। ये पहल जल आपूर्ति में सुधार, जैव-उपचार (बायो-रीमेडिएशन) के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन और खेल बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित हैं, जिनमें रख बाग में एक ऑल वैदर अत्याधुनिक स्विमिंग पूल का निर्माण भी शामिल हैं। मुख्य सड़क और पुल परियोजनाएँ भी प्रगति पर हैं, जिससे शहर में सुगम यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा, 18.08 करोड़ रुपये की लागत से 3 परियोजनाएँ निविदा प्रक्रिया (टेंडरिंग) के चरण में हैं, जिनमें नेहरू रोज गार्डन का विकास, सीवरेज मशीनरी की उन्नति और पार्कों में सुधार कार्य शामिल हैं। ये परियोजनाएँ शहर के सौंदर्यीकरण और स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

जालंधर देहाती पुलिस ने 24 घंटों में सुलझाया फर्जी डकैती का मामला

फर्जी डकैती की कहानी रचने वाला डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार

• **जालंध ब्रीज.** जालंधर

जालंधर देहाती पुलिस ने एक डिलीवरी एजेंट को गिरफ़्तार किया है, जिसने कंपनी के पैसो की चोरी को छिपाने के लिए 28,000 रुपए की लूट होने की झूठी रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने आधुनिक जांच तकनीकों का प्रयोग करते हुए 24 घंटों के अंदर केस को हल कर लिया। एसएसपी जालंधर देहाती हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि यह मामला एसपी इन्वेस्टिगेशन जसरूप कौर बाठ और डी.एस.पी. शाहकोट ओंकार सिंह बराड़ के नेतृत्व नीचे हल किया गया है। इंस्पेक्टर बलविन्दर सिंह भुल्लर, एस.एच.ओ. शाहकोट ने जांच टीम का नेतृत्व किया।

पुलिस ने रूपेवाल गाँव के तरसेम लाल के पुत्र लवनीश कुमार उर्फ दीपू को गिरफ़्तार किया है। कुमार पिछले डेढ़ महीने से सुखजीत अस्पताल नकोदर नज़दीक एक कंपनी में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, जिसके साथ वह 10,000 रुपए प्रति महीना कमा रहा था। उसने एक झूठी पुलिस शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें दावा किया गया था कि एक स्विफट कार में सवार तीन व्यक्तियों ने उसको एस.डी.एम. कोर्ट शाहकोट फ्लाईओवर के नज़दीक लूट लिया था। एसएसपी ने बताया कि जांच से पता लगा कि उस दिन कोई डकैती नहीं हुई। कुमार ने कंपनी के पैसे अपने पास रखने के लिए कहानी बनाई थी। पुलिस टीम ने कुमार के कब्ज़े में से 10,000 रुपए और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने थाना शाहकोट में धारा 304 (3 और 5 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

521 नशीली गोलियों सहित तीन तस्कर काबू

जालंधर देहाती पुलिस ने 24 घंटों के अंदर दो अलग-अलग मामलों में तीन व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर 521 नशीली गोलियां ज़ब्त की है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए दो वाहनों को भी ज़ब्त कर लिया है। एसएसपी जलंधर देहाती हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि पहली सफलता तब मिली जब मकसूदां पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने रायपुर रसूलपुर नहर नज़दीक एक स्विफट डिज़ायर कार (जेके- 02- बीएल- 3289) को रोका। उन्होंने बताया कि टीम ने हरगोबिन्द नगर के जसवीर सिंह और काहनपुर के लखवीर कुमार को गिरफ़्तार किया। उन्होंने बताया कि इनके कब्ज़े से 250 संतरी रंग की नशीली गोलियां भी बरामद की गई। एक अन्य कार्यवाही में सदर नकोदर पुलिस टीम ने बोपाराए कलाँ गाँव नजदीक शरकपुर के विक्रमजोत सिंह उर्फ बिक्का को काबू किया। यह व्यक्ति, जो एक काले ऐफज़ैड मोटरसाईकल (पीबी- 10- डीसी- 6075) पर सवार था, को 271 नशीली गोलियों सहित पकड़ा गया।

अंतर ज़िला हाईवे डकैती गिरोह का पर्दाफाश, दो काबू

जालंधर देहाती पुलिस ने एक डकैती गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ़्तार कर उनके कब्ज़े से मोबाइल फ़ोन व नकदी सहित चोरी की चीजें बरामद की है। कथित आरोपियों ने नशे की आदत को पूरा करने के लिए चोरियां की थी। एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि डीएसपी सरवण सिंह बल्ल की निगरानी में एसएचओ फिल्लौर संजीव कपूर के नेतृत्व में फिल्लौर पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने फिल्लौर के ऊँची घाटी के रहने वाले राहुल और फ़िरोज़पुर जिले के गाँव बुल्ले के रहने वाले लवप्रीत सिंह को गिरफ़्तार किया। तलाशी दौरान पुलिस ने उनके कब्ज़े में से दो चोरी किए मोबाइल फ़ोन, अपराधों में इस्तेमाल की गई एक लोहे की दातर और 900 रुपए नकदी बरामद की है।

अनाधिकृत कॉलोनियों पर चला कपूरथला प्रशासन का पीला पंजा

• **जालंधर ब्रीज.** कपूरथला

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) कपूरथला नवनीत कौर बल्ल द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए डिच मशीन का प्रयोग करके अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। अमरिंदरजीत सिंह, सहायक नगर योजनाकार एवं रैगूलेटरी टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेगोवाल में, बेगोवाल से टांडा रोड एवं जिला नगर योजनाकार, कपूरथला की सीमा बन रहे अनधिकृत कॉलोनी को पापरा एक्ट 1995 का उल्लंघन करने के लिए ध्वस्त कर दिया गया।

एडीसी ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार बेगोवाल में विकसित अनाधिकृत कालोनी को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके डैमोलीशन की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनाधिकृत कालोनी के मालिक द्वारा सरकार की हिदायतों की अनदेखी करके सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हैं।

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), कपूरथला ने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रैगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर कपूरथला जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर संबंधित थाना प्रभारी को आगामी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

इस अवसर पर उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे सरकार से मंज़ूरशुदा न होने वाली अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले कालोनी द्वारा जारी स्वीकृति अवश्य लें ताकि उनकी सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचे और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुडा क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले जितनी भी अनाधिकृत कालोनियों के लिए आवेदन किया गया है, वे कालोनाइजर जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर तुरंत अपनी कालोनियों को रेगुलर करवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पीएपी कैंपस में होगी राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप-2025

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

भारतीय घुड़सवारी फैडरेशन, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप-2025 (टैंट पेगिंग), दिनांक 15 फरवरी से 23 फरवरी 2025 पीएपी जालंधर में कैम्पस में करवाने के लिए पंजाब पुलिस को अलाट की गई है। पंजाब में तीसरी बार यह चैंपियनशिप होने जा रही है। इससे पहले साल 2016 और 2017 में पीएपी परिसर, जालंधर में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप (टेंट पेगिंग) का आयोजन किया गया था। गौरव यादव, आईपीएस, डायरैक्टर आफ पुलिस, पंजाब, पंजाब पुलिस की तरफ से करवाई जा रही राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप के मुख्य पैटरन है और एमएफ फारूकी, आई.पी.एस. आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं इंदरबीर सिंह, आई.पी.एस. डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस, प्रशासन, पीएपी आयोजन सचिव हैं। गुरतेजिंदर सिंह पीपीएस, कमांडेंट, 7वीं बटालियन पीएपी शो सैक्रेटरी है। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह 15 फरवरी 2025 को पीएपी में होगा। जिसमें गौरव यादव, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक, पंजाब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस बार इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रांतीय पुलिस घुड़सवारी टीमें, सेना, अर्धसैनिक बलों की टीमें पंजाब पुलिस क्लबों की 15 टीमों के कुल 125 घोड़े और घुड़सवार भाग लेंगे। इस चैंपियनशिप में घुड़सवारी टीम भी अपने 20 खिलाड़ियों के साथ भाग लेगी। इंद्रबीर सिंह, आईपीएस के नेतृत्व डीआइजी, प्रशासन, पीएपी करेगें। इस बार दिलचस्प और अनोखी बात यह होगी कि पंजाब पुलिस की तरफ से कोई आईपीएस अधिकारी राष्ट्रीय घुड़सवारी चैम्पियनशिप में भाग लेंगे। इस चैंपियनशिप में 2 अलग-अलग टीमों के 15 से 20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। नैशनल टेंट पेगिंग चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों में वर्ष 2025-26 के दौरान होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से भारतीय टीम का चुनाव किया जाएगा। चैंपियनशिप देखने आने वाले दर्शकों के लिए कोई टिकट और एंट्री मुफ्त होगी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य विधानमंडल परिसर में 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्य सरकार के मंत्री और विधानसभा के सदस्य इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हरियाणा की 15वीं विधान सभा के सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन लोक सभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा हरियाणा विधान सभा सचिवालय के सहयोग से किया जा रहा है। 1981 में अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित पहले प्रबोधन कार्यक्रम के बाद से PRIDE ने अब तक 70 प्रबोधन पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें राज्य विधान सभाओं के 5032 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया है।

ई-डीएआर सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन

ई-डीएआर प्रणाली हादसों की सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग, दावों के त्वरित निपटारे और बेहतर जन सुरक्षा सुनिश्चित करेगी : जसप्रीत सिंह

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

सड़क हादसों में कमी लाने और दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग तथा दावों के निपटारे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पंजाब में ई-डी.ए.आर. (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आज यहां चंडीगढ़ के मैगसीपा में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। यह सत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हिदायतों के तहत और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देश में एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) और परिवहन विभाग, पंजाब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

राज्य परिवहन आयुक्त स जसप्रीत सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान एनआईसी के विशेषज्ञों द्वारा ई-डीएआर प्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इस दौरान अधिकारियों को ई-डीएआर प्रणाली की प्रभावी डेटा एंट्री प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया, जिससे हादसों की समयबद्ध और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया से मैडम वसुंधरा ने हिट एंड रन मामलों से निपटने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी, जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को समय पर वित्तीय मुआवजा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि ई-डीएआर प्रणाली वास्तविक समय में दुर्घटनाओं से जुड़े आंकड़े एकत्र करने में सक्षम बनाएगी, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि दावों की सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ितों और उनके परिवारों को अधिक कुशलता से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। इस पहल से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को बिना किसी देरी के बेहतर चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जा सकेगी। डेटा-आधारित विश्लेषण अधिकारियों को पंजाब में सड़क हादसों की संख्या कम करने के लिए प्रभावी रोकथाम उपाय लागू करने में मदद करेगा। इस प्रशिक्षण के दौरान हादसों की वैज्ञानिक तरीके से जांच, दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज और दावों के निपटारे सहित महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य पंजाब में सड़क हादसों की अधिक कुशल और पारदर्शी रिपोर्टिंग और दावों के निपटारे से संबंधित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना है।

पंजाब सरकार जल्द ही 111 बागवानी विकास अधिकारियों की करेगी भर्ती

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने 111 बागवानी विकास अधिकारियों (एच.डी.ओज) की भर्ती को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस पहल का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना, किसानों को सहयोग देना और राज्य में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है।

बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा इन 111 बागवानी विकास अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक विवरण पंजाब लोक सेवा आयोग (पी.पी.एस.सी.) को भेजे जाएं। मंत्री ने कहा कि बागवानी विकास अधिकारियों की भर्ती किसानों को तकनीकी दक्षता, आधुनिक खेती के अभ्यास और बेहतर सहायता सेवाएं प्रदान कर बागवानी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों की भर्ती से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर गंभीर ने कहा- हमेशा खलेगी कमी

स्पोर्ट्स डेस्क. टीम इंडिया के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए हैं। वह पीठ के निचले हिस्से में चोट से जूझ रहे हैं। बुमराह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पांचवें और आखिरी टेस्ट के दौरान चोटिल हुए थे। बुमराह के 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने हाल ही में अपडेटेड भारतीय स्क्वॉड से उनका नाम हटा दिया। उनके रिप्लेसमेंट के रूप में पेसर हर्षित राणा आए हैं। अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर चुप्पी तोड़ी है।

गंभीर ने अहमदाबाद में तीसरे वनडे के बाद कहा कि जाहिर है कि वह बाहर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको सारी डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि ये मेडिकल टीम पर निर्भर करता है कि वह कितने समय तक बाहर रहेंगे। एनसीए में मेडिकल टीम ही निर्णय लेती है। कोच ने कहा कि हम उन्हें टीम में चाहते थे। हम जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। वह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। हालांकि, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। ये युवा खिलाड़ियों, जैसे हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के लिए एक अवसर है। कभी कभी ये ऐसे अवसर होते हैं जिनकी आपको तलाश होती है। हर्षित ने पूरी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कुछ अहम विकेट लिए हैं। हम सभी जानते हैं कि अर्शदीप क्या कर सकते हैं। हां, बुमराह की कमी हमेशा खलेगी। भारत ने मंगलवार को अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड में दो बदलाव किए। हर्षित के अलावा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की स्क्वॉड में एंट्री हुई है। उन्हें बल्लेबाज जायसवाल की जगह शामिल किया गया।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का अपडेटेड स्क्वॉड : रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा।

फोटो-बीसीसीआई

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.